Minister. We have not received any reply from the Prime Minister or from the Home Minister....(*Interruptions*)....Let the Home Minister tell us as to what is going on in Ayodhya. Mr. Home Minister, I am asking you ....(*interruptions*).... What is your latest report? What is going on in Ayodhya? (*interruptions*).....just tell me....(*interruptions*).... Do you have any report on Ayodhya? If tomorrow something happens, the parliament will be responsible, the Members of parliament who are the representatives of the people will be responsible. You cannot take the lives and property of some people for granted. What is going on in Ayodhya it is a very, very serious matter.....(*interruptions*).... We cannot play with the lives and property of the people ....(*interruptions*)....

उपसभापतिः आप बैठिये **(व्यवधान)** चिट्ठी लिखी है तो उसका जवाब आने दिजिये **(व्यवधान)** यादव जी आप बोलिये। **(व्यवधान)**

श्री जर्नादन यादवः पहले आप इनको बैठाइये **(व्यवधान)**

SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* Meem Afzal: Madam, the Central Government is responsible because Uttar Pradesh is under the president's rule. The Minister of State for Home Affairs is sitting in the House. He must tell us as to what is going on in Ayodhya. Thousands of people gathered there. People belonging to a particular section are being harassed by the police...*Interruptions*)...

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार): बिहार में बाढ़ में हजारों लोग मर चुके हैं **(व्यवधान)** इसके लिए कालिंग अटेंशन नोटिस दिया गया है क्योंकि बिहार में हजारों लोग मर चुके हैं **(व्यवधान)** हजारों लोग बाढ़ में मर चुके हैं **(व्यवधान)** इसके बारे में काल अटेंशन मोशन लाया गया है **(व्यवधान)**

SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Madam, the Minister should tell us as to what is going on in Ayodhya. The silence of the Government implies that something wrong is going on in Ayodhya. if something happens tomorrow in Ayodhya, the Government will be responsible.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. Afzal Saheb, Please sit down. No, I am not allowing Nothing will go on record.

...(*Interruptions*)...

श्री जगदीश प्रसाद माथुरः*

श्री विष्णु कान्त शास्त्रीः*

श्री मोहम्मद अफ़ज़ल ऊर्फ मीम अफ़ज़ल*

श्री विष्णु कान्त शास्त्री*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shastriji, please sit down, Afzal Saheb, Please take your seat. I have already said that it is not going on record. Please sit down...(*interruptions*)...बोलिये यादव जी।

श्री जर्नादन यादवः इनको तो बैठाइये। **(व्यवधान)**

उपसभापतिः मैं कैसे बैठाऊं। कोई भी नहीं बैठ रहा है। (व्यवधान) आप बैठिये **(व्यवधान)** प्लीज़ सिट डाऊन।

यादव जी आप बोलिये।

Calling Attention to a matter of Urgent Public Importance

Situation Arising out of Recent Devastating Floods in Different Parts of the Country and The steps taken by Government in Regard There to

श्री जर्नादन यादव (बिहार) उपसभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से देश के विभिन्न भागों में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं।

(उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) पीठासीन हुई

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरबिन्द नेताम) उपसभाध्यक्ष महोदया, इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तर-पूर्वी राज्यों और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल तथ सिक्किम को ओर बढ़ा, जहां यह 5 जून, 1995 वं पहुंचा। यह 8 जून को केरल पहुंचा। शुरू में मानसू मन्दा रहा और जून के अन्त तक, मौसम संबंधी 3

उप-मंडलों में से केवल 15 उप-मंडलों में अत्यधिक अथवा सामान्य वर्षा हुई और बहुत से उप-मंडलों में सामान्य से कम वर्षा हुई। जून के दौरान, केवल उत्तर-पूर्वी राज्यों में भारी वर्षा हुई। जुलाई के दूसरे सप्ताह में मानसून में कुछ तेजी आई। जुलाई और अगस्त के दौरान देश के अधिकतर भागों में वर्षा बहुत ही सुवितरित थी। अगस्त के अन्त तक, 30 से अधिक मौसम संबंधी उप-मंडलों में वर्षा अधिक अथवा सामान्य थी। वर्षा के एक बार शुरू होने के बाद, वर्षा लगातार पड़ती रही। मानसून के समाप्त होने पर, मौसम संबनधी 35 उप-मंडलों में से 32 में अधिक अथवा सामान्य वर्षा हुई। देश के लगभग 92 प्रतिशत क्षेत्र और 80 प्रतिशत जिलों में सामान्य अथवा अधिक वर्षा हुई।

इस वर्ष बंगाल की खाड़ी वाले पेत्र में समुद्री तूफान की घटनाएंअधिक रही हैं। मई के पहले और दूसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में तीन बार मानसून का दबाव बना और इसमे और अधिक तेजी आने के कारण तमिलनाडु के कुछ जिलों और आन्ध प्रदेश तथा उड़ीसा के अधिकतर तटीय जिलों में भारी वर्षा आई,पानी खड़ा हो गया और बाढ़ आ गई। पश्चिम-बंगाल, मिजोरम और उत्तर-पूर्व के कुछ अन्य राज्यों में भी काफी भारी वर्षा हुई। सितम्बर में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में मानसून के दो बार दबाव बने और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सिक्किम, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में व्यापक वर्षा हुई। मानसून के दौरान कम दबाव वाले चार क्षेत्र भी बने और इस कारण देश के केन्द्रीय और उत्तर-पश्चिमी भागों में सुवितरित वर्षा हुई। इसके बाद, अक्तूबर और नवम्बर में बंगाल की खाड़ी में पुनः सुस्पष्ट कम दबाव वाले क्षेत्र बने जिसके कारण आन्ध प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के बहुत से भागों में भारी वर्षा हुई।

दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान, उत्तर-पूर्वी राज्यों में जून के पहले पखवाड़े में बाढ़ें आई। जुलाई के दूसरे पखवाड़े में जम्मू तथा कश्मीर के बुहत से भागों में बाढ़ें आई। अगस्त के अन्तिम सप्ताह के दौरान, उत्तर-पश्चिमी भारत के अधिकतर भागों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में बाढें आई। सितम्बर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी राज्य बाढ़ से प्रभावित हुए। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 23 राज्यों में मानसून की बाढ़ का कमोवेश प्रभाव पड़ा जिनमें लगभग 2341 जानें गई और लगभग 22.00 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए और 43.00 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा।

मेरे वरिष्ठ कृषि मंत्री डा० बलराम जाखड़जी ने मैंने आन्ध प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा और पंजाब के कुछ बाढ़ और समुद्री तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मैं स्वयं पश्चिम बंगाल के कुछ प्रभावित क्षेत्रों में गया। अन्य मंत्रियों तथा माननीय संसद सदस्य ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया1 लाखों प्रभावित लोगों, विशेषकर समाज के गरीब वर्ग के लोगों की परेशानियों की हम सभी को बहुत चिन्ता है। यह सन्तोषजनक बात हैं कि राज्य सरकारों ने समय को मांग के अनुसार प्रभावित लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के आने पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राहत व पुनर्वास उपाय किए जाते हैं। भारत सरकार इस स्थिति से प्रभावी ढंग से निपनटने के लिए राज्य सरकारों को भौतिक तथा वित्तीय सहायता मुहैया करती है। दसवें वित्त आयोग ने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया है और बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को चुनौतियों को नियंत्रित करने में राज्य सरकारों को अधिक स्वायत्ता तथा उत्तरदायित्व सौंपा है। दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित राहत व्यय के वित्तपोषण की वर्तमान योजना में राज्य सरकारों के लिए बढ़े हुए वार्षिक आवंटन के साथ आपदा राहत निधि पद्धति को जारी रखा गया है। 1995 से 2000 तक के पांच वर्षों के लिए नौवें वित्त आयोग द्वारा आवंटित 4,020 करोड़ रुपए की तुलना में 6,304 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। राज्य सरकारों के लिए धार्मिक आपदा राहत निधि का आवंटन पूर्व में प्राकृतिक आयदाओं पर किए गए व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर किया गया है। 1995-96 के दौरान, आपदा राहत निधि में 1,130 करोड़ रुपए उपलब्ध है। अथवा राहत निधि के केन्द्रीय अंश की कुल 636.00 करोड़ रुपए की तीन किस्तें पहले ही सभी राज्य सरकारों को रिलीज की जा चुकी हैं इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय अंश की चौथी मासिक किस्त बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों को अग्रिम तौर पर रिलीज को जा चुकी है।

दसवें वित्त आयोग ने अत्यन्त गम्भीर किस्म की आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने की आवश्यकता को भी माना है। ऐसी स्थितियों में राज्य सरकारों को, आपदा राहत निधि योनजा में की गई व्यवस्था से अधिक सहायता तथा मदद की आवश्यकता होती है। संकट की घड़ी में राष्ट्रीय एकता का यह एक नमूना है। पांच वर्षों के लिए 700.00 करोड़ रुपए के

आवंटन के साथ अब एक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष उपलब्ध है। ताकि अत्यन्त गंभीर प्रकृति की आपदाओं के समय राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता दी जा सके। निधि की व्यवस्था कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आपदा राहत समिति द्वारा की जाती है जो राष्ट्रीय विकास परिषद की एक उप-समिति है। चालू वर्ष के दौरान हमें आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल, प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जम्मू व कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिससे वे बाढ़ से उत्पन्न गम्भीर स्थिति से निपट सकें। हमने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने तथा स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय दल प्रतिनियुक्ति किए थे। केन्द्रीय दलों की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय आपदा राहत समिति ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मिजोरम, उड़ीसा और पंजाब राज्यों को राष्ट्रीय आपादा राहत कोष से सहायता मुहैया करने का निर्णय लिया है। समिति बाकी राज्यों के अनुरोध पर जल्दी ही विचार करेगी।

महोदय, मैं हाल ही में आई बाढ़ो के कारण देश के बहुत से लोगों को हुई तकलीफों के बारे में सदन की चिन्ता से पूर्ण रूप से सहमत हूं। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत सरकार राज्य सरकारों को इस स्थिति से निपटने के लिए सभी सम्भव सहायता देगी।

श्री जनार्दन यादव: उपसैभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान बिहार की ओर ले जाना चाहता हूं और बिहार के 22 जिलों में से जो सब से अधिक प्रभावित जिला है वह बांका है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ देश के उन क्षेत्रों में आती है जहां समुद्री किनारा है या गंगा है या कोसी है या कमला बलान है या ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। प्रत्येक वर्ष बाढ़ से लोग प्रभावित होते हैं लेकिन 27 और 28 सितम्बर को जो बाढ़ बिहार में और उन क्षेत्रों में प्रवेश की जहां 200 वर्षों का इतिहास है कि दुमका से ले करके बांका तक बाढ़ का नाम लोग सुनते ही नहीं थे, बाढ़ यानी गंगा के उत्तरी भाग में, हम लोग बिहार के रहने वाले है, गंगा से प्रभावित एरिया में बाढ़ होती थी फसल बर्बाद होती थी, घर बर्बाद होते थे मनुष्य मरते थे, मवेशी मरते थे, लेकिन भागलपुर और जिला का दक्षिणी भाग जो संथाल परगना और छोटा नागपुर का एरिया है उसमें बाढ़ कभी नहीं आई थी। 27 और 28 सितबर को बाढ़ से जो गिरिडीह से ले करके भागलपुर, साहिबगंज, दुमका, गोरडा, देवधर, जमूही, मुंगेर, बांका, कटिहार और पूर्णिया जो प्रभावित हुए हैं उस प्रभाव को देखते हुए बांका में एक लाख 80 हजार मिट्टी के मकान इस बाढ़ में बह गए हैं। उसी प्रकार से 300 मनुष्य उस बाढ़ में डूब करके मर गए। दस हजार से ज्यादा मवेशी उस बाढ़ में बह करके मर गए। 128 तटबंध टूट चुके हैं। अब बांका शहर जो जिला का केन्द्र है आने के लिए, चांदन नदी पर एक पुल था वह पुल टूट कर बह गया। डेढ़ किलोमीटर की वह नदी है। आज बांका के लोग भागलपुर नहीं जा सकते, डुमका नहीं जा सकते, देवधर नहीं जा सकते यानी भागलपुर ट्रेन पकड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बांका शहर में एक पुल था जमुआजोड़ जो बांका के दो भागों को जोड़ता था वह पुल टूट चुका है। उसी प्रकार से भागलपुर जिला का जो कहलगांव प्रखंड है वहां रेलवे भागलपुर से कलकत्ता तक लोग रेल से जाते हैं, आसाम जाते हैं। एक कोआ पुल है रेल का वह टूट चुका है। अब उस रेलवे पुल के टूटने से आवागमन रेल का बंद है। अभी-अभी मैं वहां गया था उस पुल का थोड़ा सा निर्माण किया है और जीरो माइल से गाड़ी पार होती है। मैंने पूछा कि जीरो माइल से जो गाड़ी पार हो रही है अगर कोई ड्राईवर उस जीरो माइल से तेज गति से गाड़ी ले जाए तो क्या होगा तो वहां जो रलवे विभाग के लोग थे उन्होंने कहा कि गाड़ी पुल के नीचे चली आएगी।

तो इस प्रकार का बाढ़ का प्रलयंकर भारी विनाश का जो कारण हुआ उस कारण को तो हम बाद में देखेंगे लेकिन जो वहां एक लाख दस हजार घर पानी में फंस गए हैं और चार से पांच लाख की आबादी वह इस ठंड में बिना अन्न के, बिना घर के रह रही है। यह आश्चर्यजनक बात है कि बांका की 14 लाख आबादी में से 5 लाख आबादी के पास घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है।

पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए कोई छत नहीं है और इस जाड़े की रात्रि में वह बाहर सो रहा है। महोदया, केन्द्र सरकार के मंत्री जी ने बयान में कहा कि राहत कोष का काम हुआ है। महोदया, 11 अक्तूबर को मैं दिल्ली आया था। अब बिहार सरकार ने इस के लिए क्या किया, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री जी विदेश दौरे पर थे। मैं प्रधान मंत्री जी से मिलने आया था कि कम-से-कम इस आपात स्थिति में प्रधान मंत्री जी से मिलकर बांका, कोड्डा, दुमका, देवघर, मुंगेर, भागलपुर, पुर्णिया, कटिहार, साहिबगंज में जो बाढ़ से क्षति हुई है, बाढ़ से जो लोग परेशान हुए हैं, उस से लोगों को राहत मिले, इसलिए मैं

*Not recorded.

आया था। मैं तीन दिनों तक पी०एम० ऑफिस में टेलीफोन करता रहा कि प्रधान मंत्री जी से भेंट कराओ, बात कराओ लेकिन पी०एम० ऑफिस से सूचना नहीं मिली। महोदया, इस देश में भगवान से मिलना सरल है, लेकिन वर्तमान प्रधान मंत्री से मिलना बड़ा कठिन है। हम ने एक पत्र लिखकर दिया कि अगर राज्य सरकार द्वारा कराए गए सर्वे पर आप को विश्वास नहीं है तो कम-से-कम केन्द्रीय दल भेजकर के जिन 22 जिलों में बाढ़ आई उस में 7 जिलों बांका, कोड़ा, दुमका देवगढ़, जमुही, मुंगेर, साहिबगंज, भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार जोकि 27-28 सितंबर की बाढ़ से प्रभावित हुए, उन का तो सर्वे करा लीजिए। महोदया, मैं कल-परसों बांका गया था। वहां सेंट्रल टीम पहुंची थी और बांका शहर में जो दो पुल थे उन्हें देखकर लौट आई, लेकिन उन्होंने जहां 16 हजार हैक्टेयर जमीन बांका की बाढ़ के चलते बालूमय हो गयी और फसल बर्बाद हो गयी, वहां जाकर देखने का कष्ट नहीं किया।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): यादव जी, आप अपना भाषण बाद में कंटीन्यू करिए।

I now adjourn the House till 2 p.m.

The House, then, adjourned at thirty two minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at five minutes past two of the clock.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA) in the Chair]

RE. BOMB HOAX IN PARLIAMENT HOUSE

DR. BIPLAB DASGUPTA (WEST BENGAL): Madam, I understand that there has been a bomb scare and I hope that that bomb scare has been proved to be a hoax. There is no bomb in the Hall. But I am more worried about some *who are there in the hall. And if they explode then nothing can save us. Today is the 5th of December, tomorrow will be the 6th of December. Three years ago some of those who are sitting here had been the *who exploded the Babri Masjid. I am saying this just to remind you that tomorrow no BJP Member should be allowed in because I do now know.....*(Interruptions)*

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (UTTAR PRADESH): I object to the remark made by Dr. Biplab Dasgupta. *(Interruptions)* The Calling Attention Motion is under discussion. *(Interruptions)*

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): काले कुत्ते देख रहे थे उनको कुछ नहीं मिला।

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): मैडम,

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): यह तो होक्स था, हो गई बात खत्म।

श्री जनेश्वर मिश्र: नहीं मैडम/ आपके आसन से हम लोगों से कहा गया कि आप लोग जल्दी से सदन को खाली कर दीजिए। इस सदन का सदस्य होते हुए और हम लोग इस महान देश के प्रतिनिधि माने जाते हैं और उस हालत में ऐसे बोल दिया जाए, यह मामूली घटना नहीं है। सैंट्रल हॉल में जाने के बाद हमको मालूम पड़ कि यहां कहीं बम रखा है और जांच होने वाली है।.... **(व्यवधान)**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): कोई टेलीफोन आया था।

श्री जनेश्वर मिश्र: ऐसे बम हिन्दुस्तान की सरहद प हमारे सिपाही अपने सीने पर बहुत झेलते है। यह सद बहुत बड़ी जगह है। अगर यहां से यह मैसेज चला जा कि मामूली टेलीफोन के आने पर पार्लियामेंट के मेंबर सदन छोड़कर चले जाते हैं तो यह मत समझिएगा कि मुल्क के सामने एक अजीब किस्म का चरित्र निर्मा होगा और वह शर्मनाक होगा। जिस किसी ने यह हरक की, मैं नहीं जानता कि गृह मंत्रालय का यहां कोई है नहीं, लेकिन जिस किसी ने यह हरकत की उसके बारे क्या कार्रवाई हो रही है और यह वातावरण संसदी जनतंत्र में दुनियां में कहीं भी नहीं है। हिन्दुस्तान का एक लड़का लंदन के पार्लियामेंट में बम फैकने गया था, य तो सुनने को मिला था, लेकिन हिन्दुस्तान की संसद और दुनियां की संसद में इस तरह की घटना कहीं सुन को नहीं मिली। बहुत ही शर्मनाक है और इसके लि होम मिनिस्टर को जिम्मेदारी लेकर के बयान देना चाहि कि वे क्या कार्रवाई कर रहे है? टेलीफोन भी इस तर के फेक आते हैं तो उसकी टेलीफोन डिपार्टमेंट जांच क सकता है, कार्रवाई कर सकता है, वरना ऐसे घटनाएं रो होने लगेंगी, तो यह सदन नहीं चल सकता और संसदी जनतंत्र भी नहीं चलेगा। अगर असली बम आएगा त संसदीय जनतंत्र चलेगा कि नहीं, यह एक बहुत बड़ प्रश्नचिन्ह लग गया है। इसलिए मैडम, मैं चाहूंगा कि इसको गंभीरता से लिया जाए। जैसे आपने कह दिया कि इसको छोड़िए, यह छोड़ने लायक विषय नहीं है।